



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रार्थिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 470]
No. 470]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 4, 1989/भाद्र 13, 1911
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 4, 1989/BHADRA 13, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

विद्युत मंत्रालय
(रास्व विभाग)
(विदेश कर विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1989

आय-कर

मा.का.नि. 812 (अ).—आय-कर के वृद्धि करारान के परि-
वर्जन के लिए भारत गणराज्य की सरकार और सोवियत समाजवादी
गणराज्य संघ की सरकार के बीच उपावख करार, उक्त करार के अनुच्छेद
28 के अनुसार उक्त करार को प्रवृत्त करने के लिए उनकी अपनी विधियों
के अधीन अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा किए जाने की दोनों संविदाकारी
राज्यों द्वारा एक दूसरे को अधिसूचना के पश्चात्, 5 जून, 1989 को
प्रवृत्त हुआ है।

अब, अतः केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1931 (1931
का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह
निर्देश देती है कि उक्त करार के सभी उपबंधों को भारत संघ में प्रभावी
किया जाएगा।

उपाबंध

आय पर दोहरे कराधान के परिहार के लिए
भारत गणराज्य की सरकार

और

सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की सरकार
के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार और सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ
की सरकार ने आर्थिक, औद्योगिक, तकनीकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में
सहोपपूर्ण संबंधों को मजबूत बनाने और उनका विकास करने की इच्छा
से प्रेरित होकर आय पर दोहरे कराधान के परिहार के लिए
एक करार निष्पन्न करने का फैसला किया है और वे नीचे लिखे अनुसार
सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद 1

करार का क्षेत्र

1. यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो कराधान के प्रयोजनों
के लिए एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी समझे जाते हैं।

2. (क) यह करार प्रत्येक संविदाकारी राज्य के क्षेत्र पर, जिसमें उसके क्षेत्रीय समुद्र शामिल हैं, उसके आर्थिक क्षेत्र पर और उसके क्षेत्रीय समुद्र की सीमाओं के निकटवर्ती उसके ऐसे महादीप्य शेलफ पर, जिसके संबंध में वह अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप ऐसे क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों की खोज तथा उनके समुपयोजन के प्रयोजन के लिए प्रभुत्व प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करता है, लागू होगा।

(ख) इस करार के प्रयोजनों के लिए दोनों संविदाकारी राज्यों का कोई भी हवाला उनके अपने-अपने राज्य के क्षेत्रीय जिसमें उसके क्षेत्रीय समुद्र शामिल हैं, उसके आर्थिक क्षेत्र और उसके राज्य के क्षेत्रीय समुद्र की सीमाओं के निकटवर्ती महादीप्य शेलफ के क्षेत्र, जो उप-पैराग्राफ (क) में उल्लिखित हैं, के संबंध के रूप में समझा जाएगा।

अनुच्छेद 2

करार के अंतर्गत आने वाले कर

1. जिन करों पर यह करार लागू होगा, वे इस प्रकार हैं:

(क) भारत गणराज्य में, आयकर जिसमें उस पर लगने वाला कोई भी अधिभार शामिल है;
(जिन्हें इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा)

(ख) सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ में;

(i) विदेशी विधिक व्यक्तियों पर आयकर;

(ii) जनसंख्या पर आयकर;

(iii) किसी संयुक्त उद्यम के किसी विदेशी भागीदार के लाभों के भाग पर लगाया गया कर, जब वह देश से बाहर अन्तर्गत किया जाता है।

(जिन्हें इसके बाद "सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ कर" कहा जाएगा)।

2. यह करार किसी भी समरूप अथवा भारत: इसी तरह के करों पर भी लागू होगा, जो दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा मौजूदा करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएं।

3. इस अनुच्छेद में उल्लिखित करों में इस करार के अंतर्गत आने वाले करों के संबंध में दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा लगाया गया कोई अर्थव्यय अथवा ब्याज शामिल नहीं होगा।

अनुच्छेद 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार में जब तक कि विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "एक संविदाकारी राज्य" और "दूसरा संविदाकारी राज्य" पदों से विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार भारत गणराज्य (भारत) अथवा सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ (यू.एस. एस.एर.) अभिप्रेत है।

(ख) "व्यक्ति" शब्द से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति, और

(i) भारत के मामले में, कोई कंपनी अथवा कोई अन्य सत्ता, जिसे भारत में लागू कराधान कानूनों के अंतर्गत एक कर-योग्य एकक के रूप में समझा जाता है;

(3) सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के मामले में सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ अथवा किसी संघ गणतंत्र के कानूनों के अंतर्गत उत्पन्न तथा सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ में कराधान के प्रयोजनों के लिए किम

विधिक व्यक्ति के रूप में समझा गया कोई विधिक व्यक्ति अथवा अन्य संगठन भी;

(ग) "मक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है:

(1) भारत के मामले में, वित्त मंत्रालय (केन्द्रीय सरकार राजस्व विभाग) अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(2) सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के मामले में सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ का वित्त मंत्रालय अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(घ) "राष्ट्रिक" शब्द से अभिप्रेत है:

(1) भारत के मामले में, भारत की नागरिकता-प्राप्त कोई व्यक्ति और भारत में प्रवृत्त कानूनों में अपनी हैसियत प्राप्त करने वाला कोई विधिक व्यक्ति, भागीदार अथवा संस्था;

(2) सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के मामले में, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की नागरिकता प्राप्त कोई व्यक्ति और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ में प्रवृत्त कानूनों में अपनी हैसियत प्राप्त करने वाला कोई विधिक व्यक्ति;

(ङ) "अन्तर्राष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है—किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित हो, सिवाय उस व्यक्ति के जब उक्त जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो।

(च) "वित्त वर्ष" पद से अभिप्रेत है:

(1) भारत के मामले में, "पूर्ववर्ती वर्ष", जैसाकि आयकर अधिनियम, 1961 में परिभाषित किया गया है।

(2) सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के मामले में, पन्द्रही जनवरी को आरम्भ होकर 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली अवधि।

2. जहां तक एक संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार के प्रवर्तन का संबंध है, किसी शब्द का, जो उसमें परिभाषित नहीं हुआ है, जब तक विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तब तक वही अर्थ होगा, जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है, जिन पर यह करार लागू होता है।

अनुच्छेद 4

निवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत है, कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिस पर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबंध-स्थान अथवा इस प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण वहां पर कर लगाया जा सकता है।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी:—

(क) उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास गृह उपलब्ध हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) हैं;

(ब) यदि उस संविदाकारी राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हिस्से निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो, अथवा यदि उसके पास दोनों संविदाकारी राज्यों में कोई भी स्थायी निवास गृह उपलब्ध नहीं हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आबतन रहता हो;

(ग) यदि वह आबतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह राष्ट्रिक है;

(घ) यदि प्रत्येक संविदाकारी राज्य उसे उस राज्य का एक राष्ट्रिक मानता है अथवा वह दोनों में से किसी भी राज्य का राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा उस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

3 जहाँ किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण, दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका वास्तविक प्रबन्ध-स्थान स्थित है।

अनुच्छेद 5

स्थायी संस्थापन

1. इस क़रा के प्रयोजनार्थ "स्थायी संस्थापन" पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है जिसके द्वारा एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी अन्य संविदाकारी राज्य में कारोबार पूर्णतया अथवा अंशतया चलाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे—

- (क) प्रबन्ध व्यवस्था का कोई स्थान,
- (ख) कोई शाखा;
- (ग) कोई कार्यालय;
- (घ) कोई कारखाना;
- (ङ) कोई कार्यशाला;
- (च) कोई खान, तेल अथवा गैस का कोई कुआँ, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान;
- (छ) कोई भाँडागार, जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों के लिए भण्डारण सुविधाएँ, मुहैया करता हो;
- (ज) कोई परिसर जो किसी बिक्री निर्गम के रूप में अथवा आर्डर प्राप्त करने अथवा याचना करने के लिए प्रयुक्त किए गए हों;
- (झ) कोई संस्थापन अथवा मरजना, जो प्राकृतिक संसाधनों की गवेषणा अथवा समुपयोजन के लिए प्रयुक्त होता हो;
- (अ) कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण, सम्पत्ति अथवा असेम्बली परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप, जहाँ ऐसा स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप (ऐसे अन्य स्थलों, परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों सहित, यदि कोई हों) 6 महीनों से अधिक की अवधि के लिए जारी रहता है अथवा जहाँ मशीनरी अथवा उपकरण की बिक्री प्रासंगिक होने वाली ऐसी परियोजना अथवा पर्यवेक्षी कार्यकलाप 6 महीनों से अधिक किसी अवधि के लिए जारी रहता है और परियोजना अथवा पर्यवेक्षी कार्यकलाप के लिए देय प्रभार मशीनरी और उपकरण के बिक्री मूल्य के 10% से बढ़ जाता है।

तथापि, संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी मामले विशेष में और उस मामले में भी, जब किसी भवन-स्थल अथवा किसी निर्माण अथवा असेम्बली परियोजना पर कार्यों की अवधि छः माह से अधिक हो जाती है और पारस्परिक करार के द्वारा ऐसे कार्यकलापों के बारे में यह मान सकते हैं कि वह स्थायी संस्थापन नहीं है।

बशर्ते कि इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन का स्वामी समझा जाएगा और यह भी समझा जाएगा कि वह उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता है यदि वह इस संबंध में सेवाएँ अथवा सुविधाएँ प्रदान करता है अथवा दूसरे राज्य में खनिज तेलों को खोजने अथवा निष्कर्षण उत्पादन के लिए उपयोग में लाई गई अथवा उपयोग में लाई जाने वाली संयंत्र और मशीनरी किराए पर मुहैया करता है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों के होते हुए भी, "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा—

- (क) निवासी की पण्य वस्तुओं के केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग,
- (ख) केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ निवासी के माल का कोई स्टॉक रखना;
- (ग) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ निवासी के माल अथवा पण्य वस्तुओं का स्टॉक रखना;
- (घ) निवासी के लिए माल अथवा पण्य वस्तुओं का केवल क्रय करने अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना;
- (ङ) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (अ) के उपबन्धों के अन्वये निर्माण और असेम्बली कार्यों पर 6 माह से अधिक अवधि के लिए केवल पर्यवेक्षण करना;
- (च) निवासी के लिए केवल विज्ञापन अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा किसी प्रारम्भिक अथवा किसी सहायक स्वरूप के कार्य को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना;
- (छ) यदा-कदा होने वाली प्रदर्शनियों में निवासी के माल और पण्य वस्तुओं के प्रदर्शन के लिए कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना;
- (ज) उप-पैराग्राफ (क) से (छ) में निर्दिष्ट एक अथवा अनेक किस्म के कार्यकलापों को निवासी के लिए कार्यान्वित करने के लिए कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना, यदि इस किस्म के कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के परिणामतः कारोबार के निश्चित स्थान के समग्र कार्यकलाप प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के हों।

तथापि उप-पैराग्राफ (क) से (ज) के उपबन्ध वहाँ लागू नहीं होंगे जहाँ तक संविदाकारी राज्य का निवासी उक्त उप-पैराग्राफों में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में कारोबार का कोई अन्य निश्चित स्थान रखता है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्धों के होते हुए भी किसी स्वतंत्र हैनियत के अधिकारी से, जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता है, जहाँ भिन्न कोई व्यक्ति दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी की ओर से एक संविदाकारी राज्य में कार्य कर रहा है, उस निवासी को प्रयोज्य संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन का स्वामी समझा जाएगा, यदि—

- (क) उसे निवासी की ओर से उस राज्य में सुविधाएँ सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आम-सौर से उस राज्य में प्राधिकार का प्रयोग करता हो, जब तक कि उसके कार्यकलाप

निवासी के लिए माल अथवा पण्य वस्तुओं की खरीद तक सीमित नहीं हो;

(ख) उनके पास ऐसा कोई प्राधिकार नहीं होगा, परन्तु वह प्रत्येक राज्य में ग्राम-तौर पर माल का अथवा पण्य वस्तुओं का कोई स्टॉक रखता हो जिसमें से वह निवासी की ओर से माल अथवा पण्य वस्तुओं की निर्यात रूप से निर्यात करता हो;

(ग) वह ग्राम-तौर पर प्रथमोक्त राज्य में निवासी के स्वयं के लिए अथवा नियंत्रण करने वाले अथवा नियंत्रित किए गए अथवा उसी ग्राम नियंत्रण के अधीन निवासी और अन्य निवासी के लिए पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः आदेश प्राप्त करता है; अथवा

(घ) इस प्रकार के कार्य में, वह निवासी के लिए निवासी का माल अथवा पण्य वस्तुओं का उस राज्य में निर्माण करता है अथवा उन्हें संसाधित करता है।

5. एक संबिदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संबिदाकारी राज्य में मात्र इस कारण से कोई स्थायी संस्थापन का स्वामी होना नहीं माना जाएगा क्योंकि वह उस राज्य में बलात्, सामान्य कर्मिण एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों।

6. यदि कोई व्यक्ति (किसी व्यक्ति से भिन्न) जो, एक संबिदाकारी राज्य का निवासी है, किसी ऐसे व्यक्ति (किसी व्यक्ति से भिन्न) को नियंत्रित करता है अथवा उससे नियंत्रित होता है, जो दूसरे संबिदाकारी राज्य का निवासी है अथवा जो दूसरे राज्य (किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से या अन्यथा) में कारोबार करता है तो मात्र इस तथ्य से ही इन दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संबिदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संबिदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति (जिसमें कृषि अथवा वानिकी की आय भी शामिल है) से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संबिदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबिदाधीन सम्पत्ति स्थित है। भारत के मामले में, इस पद में किसी भी दशा में वे शामिल होंगे—अचल सम्पत्ति के उपांग के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-संपत्ति के विषय में सामान्य कानून के उपबन्ध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, खनिज तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत प्रदायगियों के अधिकार।

जलयान, नौकाएं तथा विमान अचल सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराए पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के उपयोग से होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबन्ध, किसी निवासी की अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं की अचल सम्पत्ति के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 7

कारोबार से लाभ

1. एक संबिदाकारी राज्य के किसी निवासी के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा, जब तक कि वह निवासी दूसरे संबिदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार नहीं करता हो। यदि उक्त निवासी उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो, तो उस निवासी के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उनके केवल उतने ही अंश पर कर लगेगा, जो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उस स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न माना जा सकता है।

2. पैराग्राफ 3 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जहां एक संबिदाकारी राज्य का कोई निवासी दूसरे संबिदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के जरिए कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संबिदाकारी राज्य में होने वाले लाभों को उस स्थायी संस्थापन के लाभ समझा जाएगा, जो उसको प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहती, जब एक-समान या मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक-समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न निवासी होता और उस निवासी के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता, जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में, उन व्ययों को बटौतियों के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जो उस उक्त स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ किए गए हों, जिनमें इस प्रकार किए गए ऐसे कार्यकारी तथा प्रशासनिक व्यय भी शामिल होंगे, फिर चाहे वे उस राज्य में किए गए हों, जहां स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों, किन्तु उक्त राज्य के कराधान कानूनों के उपबन्धों के अनुसार तथा उसकी सीमाओं में रहते हुए किए गए हों।

4. किसी स्थायी संस्थापन को कोई लाभ केवल इस कारण दिया नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा निवासी के लिए माल या पण्य वस्तुएं खरीदी गई हों हैं।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ, स्थायी संस्थापन के कारण समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठीक तथा पर्याप्त कारण नहीं हों।

6. जहां लाभों में आय की वे मदें शामिल हैं, जिनका वियेचन इस कारण के अन्वय अनुच्छेदों में किया जाता है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबन्ध इस अनुच्छेद के उपबन्धों से प्रभावित नहीं होंगे।

7. जहां —

(क) एक संबिदाकारी राज्य का निवासी, दूसरे संबिदाकारी राज्य के किसी निवासी की प्रबन्ध व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है; अथवा

(ख) वहां व्यक्ति, एक संबिदाकारी राज्य के निवासी तथा दूसरे संबिदाकारी राज्य के निवासी की प्रबन्ध व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है;

तथा किसी भी मामले में ऐसे दो निवासियों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों के कारण ऐसी शर्तें बनाई अथवा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न होती जो स्वतंत्र निवासियों के लिए बनाई जाती हैं, तब उस स्थिति में ऐसी शर्तों के न होने पर दोनों निवासियों में से किसी एक निवासी को द्वारा कोई भी लाभ जो ऐसी शर्तों के होने पर पर उसे प्राप्त न हुआ होता, उक्त निवासी के लाभों में शामिल किया जाएगा और उस पर तदनुसार कराधान किया जाएगा।

अनुच्छेद 8

वायु परिवहन

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में वायुयान के परिचालन से प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त होने वाले लाभों पर भी लागू होंगे।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में वायुयान परिचालन से संबंधित विधियों पर ब्याज को वायुयान के ऐसे परिचालन से प्राप्त हुए लाभों के रूप में माना जाएगा तथा अनुच्छेद 4 के उपबन्ध ऐसे ब्याज के मामले में लागू नहीं होंगे।

4. "वायुयान परिचालन" पद से अभिप्राय वायुयानों के मालिकों या पट्टेदारों अथवा अवज्ञेलाभों द्वारा वायुयान से यात्रियों, डाक, पशुधन अथवा माल के परिवहन के कारोबार से है, जिसमें अन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री वायुयान का आकस्मिक पट्टा तथा ऐसे परिवहन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित कोई अन्य कार्यकलाप भी शामिल है।

अनुच्छेद 9

नौवहन

1. किसी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलयान के संचालन से प्राप्त हुई आय पर उस राज्य में कर लगेगा।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबन्धों तथा भारत गणराज्य की सरकार और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की सरकार के बीच मॉन्टे नेवहन के संबंध में दिनांक 19 जुलाई, 1976 को हुए करार के अनुच्छेद 15 के उपबन्धों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य की बन्दरगाहों के बीच और तीसरे देशों की बन्दरगाहों के बीच (दोनों दिशाओं में) जलयानों के संचालन से प्राप्त आय पर उक्त दूसरे राज्य में कर लगेगा लेकिन उक्त दूसरे राज्य में लगाए गए कर को दो तिहाई राशि के बराबर कम किया जाएगा।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबन्ध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलयानों के संचालन में लगी हुई एजेंसी में भागीदारी से प्राप्त हुए लाभों पर भी लागू होंगे।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ :—

(क) अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलयान के संचालन से संबंधित विधियों पर ब्याज को ऐसे जलयानों के संचालन से प्राप्त आय समझा जाएगा तथा ऐसे ब्याज के संबंध में अनुच्छेद 11 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे; और

(ख) जलयान के संचालन से प्राप्त आय में अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में माल अथवा पशु वस्तुओं के परिवहन के संबंध में आयानों (ट्रेलर तथा आयानों के परिवहन के लिए सन्नात उपकरण भी शामिल हैं।) का इस्तेमाल, उनका रख-रखाव अथवा उन्हें किराए पर लिया जाना भी शामिल है।

अनुच्छेद 10

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी विधिक व्यक्ति (भारत के मामले में कम्पनी), जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी, उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, जिसका लाभांश अदा करने वाला विधिक व्यक्ति (भारत के मामले में कम्पनी) एक निवासी है, परन्तु, यदि प्राप्तकर्ता, लाभांश का हितभागी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लाभांश की सकल राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

इस पैराग्राफ का प्रभाव उन लाभों के संबंध में विधिक व्यक्ति (भारत के मामले में कम्पनी) के कराधान पर नहीं पड़ेगा, जिनमें से लाभांशों का भुगतान किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांश" शब्द का अभिप्राय शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है, जो लाभ की भागीदारी का के अंशदावे नहीं हों और अन्य नियमित अधिकारों से प्राप्त आय से है, जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है, जो उस राज्य के कानूनों के अन्तर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है, जिसका वितरण करने वाला विधिक व्यक्ति (भारत के मामले में कोई कम्पनी) निवासी है। सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के मामले में इस पद का अभिप्राय विशेष रूप से सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के कानूनों के अनुरूप स्थापित किए गए किसी संयुक्त उद्यम के लाभों के उस भाग से है, जो सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ से स्थानान्तरित होकर आए, इसके भागीदार, जो भारत का निवासी है, को प्राप्त आय से है।

4. पैराग्राफ (1 और 2) के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभांश का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है जिसका लाभांश अदा करने वाला विधिक व्यक्ति (भारत के मामले में कोई कम्पनी) निवासी है और जिस सम्पत्ति के संबंध में लाभांश अदा किए जाते हैं, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन से प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामलों में अनुच्छेद 7 के उपबन्ध लागू होंगे।

अनुच्छेद 11

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में तथा उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगेगा, जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार प्रभारित कर की राशि ब्याज की सकल राशि के 15 प्रतिशत के अधिक नहीं होगी।

3. पैराग्राफ 2 के उपबन्धों को होते हुए भी :—

(क) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुए ब्याज पर उस देश में कर से छूट प्राप्त होगी वशत कि वह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया गया हो तथा हितभागी स्वामित्व में हो;

(i) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, कोई उप-प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण; अथवा

(ii) उस दूसरे राज्य का सेंट्रल बैंक;

(ख) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुए ब्याज पर उस राज्य में उतनी सीमा तक कर से छूट दी जाएगी, जितनी उस राज्य की सरकार द्वारा अनुमोदित की गई हो, यदि वह ब्याज किसी ऐसे व्यक्ति (पैराग्राफ (क) में उल्लिखित व्यक्ति से नितः कोई व्यक्ति द्वारा) प्राप्त किया गया हो तथा उसके हितभाग स्वामित्व में हो, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, भवित कि जिस नेत-देन से ऋणवासे उत्पन्न हुए है, उन्हें प्रथमोल्लिखित राज्य की सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया गया हो।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "ब्याज" शब्द का अधिप्राय प्रत्येक प्रकार के ऋणवाशों, बैंक निक्षेपों, सरकारी ऋणों से प्राप्त आय तथा किसी भी अन्य आय से, जिसे उस राज्य के कानूनों के अनुसार ब्याज समझा जाता है, जहां ऐसी आय उद्भूत होती हो। बिलब में की गई अदायगी के संबंध में प्रभावित अर्थव्यवस्था को इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ ब्याज नहीं समझा जाएगा।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज उद्भूत हुआ हो, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता हो और जिस ऋणवासे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो, वहां इस प्रकार के स्थायी संस्थापन से प्रभावी रूप से संबंधित हो। ऐसे मामलों में अनुच्छेद 7 के उपबन्ध लागू होंगे।

6. ब्याज एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा, जब ब्याज अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, उस राज्य का कोई उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो, किन्तु जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो, अथवा न हो, किसी संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन है, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था, जिस पर ब्याज की अदायगी की जाती है और इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन द्वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार का ब्याज उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, जिसमें वह स्थायी संस्थापन स्थित है।

7. जहां ब्याज को अदा करने वाले तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, अदा किए गए ब्याज की रकम, उस ऋण दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होनी, जहां अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगी के अनतिरिक्त भाग पर, इस प्रकार के अन्य उपबन्धों का सम्यक अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 12

रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वह उद्भूत हुई हो, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, लेकिन यदि अदाकर्ता, रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर निम्नलिखित में अधिक नहीं होगा—

(क) रेडियो अथवा टेलीविजन प्रसारण में प्रयुक्त होने वाली सिनेमा फिल्में अथवा फिल्मों अथवा टेपों से भिन्न साहित्यिक, कलात्मक

अथवा वैज्ञानिक कार्यों के प्रयोगाधिकार से संबंधित रायल्टियों की सकल राशि का 15 प्रतिशत; और

(ख) अन्य सभी मामलों में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि का 20 प्रतिशत।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टी" शब्द में से अभिप्रेत है। (साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृतियों के किसी भी कॉपीराइट) के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए, चित्रों में सिनेमा फिल्में, अथवा रेडियो अथवा टेलीविजन प्रसारण के लिए फिल्मों अथवा टेपों भी शामिल हैं, कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान अथवा फार्मूला अथवा प्रक्रिया अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्रतिकूल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद से अभिप्रेत है किमी प्रबंधकीय, तकनीकी अथवा परामर्शदात्री स्वरूप की सेवाओं के लिए, जिसमें तकनीकी सेवाओं तथा अन्य कार्यों की सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल है, प्रतिकूल के रूप में, अदायगियां करने वाले किसी व्यक्ति के किसी कर्मचारी को की जाने वाली अदायगियों में भिन्न किसी व्यक्ति को की जाने वाली अदायगियां।

5. इस अनुच्छेद के पैरा 1 और 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हित-भागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां पर स्थिति किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार चलाता है और जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति अथवा संविदा के संबंध में रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन के प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामलों में अनुच्छेद 7 के उपबन्ध लागू होंगे।

6. ऐसे संविदाकारी राज्य में रायल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी जब रायल्टी और फीस अदा करने वाला स्वयं वह एक राज्य, उस राज्य का कोई उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण या कोई निवासी हो। तथापि, जहां रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन हो, जिसके संबंध में रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने का वचन दिया गया हो, और ऐसी रायल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन स्थित है।

7. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गई रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम उस रकम से बढ़ जाती है, जितनी रकम इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा की गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदा की गई रकम के अनतिरिक्त भाग पर, इस प्रकार के अन्य उपबन्धों को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 13

सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 में यथा उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अथवा सम्पत्ति के अन्तरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी कल सम्पत्ति के अन्तरण से होने वाले लाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थान का व्यापारिक सम्पत्ति का एक हिस्सा है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अर्थात् अथवा पूर्ण सम्पत्ति के साथ) के अन्तरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा ऐसे जलयानों अथवा वायुयान के परिचालन में संबंधित चल-सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा, जिसका कि अन्तरणकर्ता निवासी है।

4. किसी विधिक व्यक्ति (भारत के मामले में एक कम्पनी) जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, के पूंजीगत स्टॉक के शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर उसी राज्य में कर लगेगा।

5. पैराग्राफ 1, 2, 3 और 4 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर उसी संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, जिसका अन्तरणकर्ता निवासी है।

अनुच्छेद 14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. किसी व्यक्ति द्वारा जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, व्यावसायिक सेवाओं अथवा उसी प्रकार के अन्य स्वतंत्र कार्यकलापों से प्राप्त आय पर, दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, बशर्ते कि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि अथवा अवधियां संगत वित्त वर्ष में कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक हों, ऐसे मामले में ऐसी आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा लेकिन आय के उतने भाग पर ही कर लगेगा जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त हुई हो।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद के अर्थ विस्तार के अन्तर्गत विशेष रूप से किसी व्यक्ति द्वारा चिकित्सक, अध्यापक, वास्तुविद, इंजीनियर तथा लेखापाल तथा चिकित्सकों की हैसियत में किए गए स्वतंत्र कार्य कलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद 15

नियोजन से आय

1. अनुच्छेद 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लगेगा, जब तक कि उसका नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में न हो। यदि नियोजन इस प्रकार होता है तो उससे उद्भूत ऐसे पारिश्रमिक पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकता है।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा, दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए नियोजन से उद्भूत पारिश्रमिक पर कर प्रथमोत्पन्नित राज्य में केवल उस स्थिति में लगाया जाएगा :

(क) प्राप्तकर्ता सम्बद्ध वित्त वर्ष में किसी उस अवधि अथवा उन अवधियों के लिए दूसरे राज्य में मौजूद रहा हो जो कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक न हो ; और

(ख) पारिश्रमिक की पराप्ती ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से की गई हो, जो दूसरे राज्य का निवासी न हो और

(ग) पारिश्रमिक व्यय का बहुत किसी ऐसे स्थायी संस्थापन द्वारा नहीं किया जाता है जो नियोजक का उस दूसरे राज्य में हो।

3. इस अनुच्छेद के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयान पर अथवा वायुयान पर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर उस राज्य में लगे सकेगा।

अनुच्छेद 16

निवेशकों की फीस

संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी के निवेशक मंडल अथवा उस कम्पनी को ऐसे ही किसी अन्य ग्रंथ के एक सदस्य की हैसियत से, अथवा किसी अन्य विधिक व्यक्ति की हैसियत में जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी हो, प्राप्त किए गए निशिक शुल्क तथा इसी प्रकार की अन्य अवयवियों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगा सकेगा।

अनुच्छेद 17

मनोरंजनकर्ताओं और खिलाड़ियों द्वारा अर्जित आय

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता, जैसे कि कोई थियेटर कल चित्त, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में इस प्रकार का प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, जिसमें उस मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को कार्यकलाप किए जाते हैं।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में उसी हैसियत से किए गए अपने व्यक्तिगत कार्यकलापों से अर्जित आय केवल प्रथमोत्पन्नित संविदाकारी राज्य में ही कर योग्य होगी, यदि ऐसे कार्यकलापों के लिए प्रथमोत्पन्नित राज्य की, जिसमें उसके अप्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं, मार्बज-निक निधियों से 50 प्रतिशत से अधिक व्यय समर्पित होते हैं।

4. पैराग्राफ 2 और अनुच्छेद 7, 14 तथा 15 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी उसी हैसियत में एक संविदाकारी राज्य में किए गए व्यक्तिगत कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय केवल मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी स्वयं को प्राप्त नहीं होती है परन्तु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो उस मामले में वह आय केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर योग्य होगी, यदि इस प्रकार के व्यक्ति के व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक भाग दूसरे राज्य की, जिसमें उसके अप्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं, सांभजनिक निधियों से समर्पित हो।

अनुच्छेद 18

सरकारी सभा के संबंध में पारिश्रमिक तथा पेंशन

1. (क) एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य के अथवा उसके उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के निमित्त प्रदत्त पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा :

(ख) लेकिन ऐसे पारिश्रमिक पर कर दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल तब लग सकेगा यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में की जाती हैं तथा वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी है जो :

(i) उस राष्ट्र का राष्ट्रिक है अथवा

(ii) मात्र सेवाएं देने के प्रयोजनार्थ उस राज्य का निवासी नहीं बना था ।

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित किए गए क्षेत्र में से किसी व्यक्ति को, उसके द्वारा उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के निमित्त की गई सेवाओं के लिए प्रदत्त किसी पेंशन पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा ।

2. (ख) तथापि, ऐसी पेंशन केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर योग्य होगी, यदि कोई व्यक्ति उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है और राष्ट्रिक है ।

3. अनुच्छेद 15, 16 और 19 के उपबंध वाणिज्यिक कार्यकलाप के संबंध में की गई सेवाओं के लिए पारिश्रमिक तथा पेंशनों पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद 19

पेंशन

एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के आन्तरिक स्त्रों से प्राप्त ऐसी पेंशन पर, जो अनुच्छेद 18 में उल्लिखित पेंशन से भिन्न है, प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में उपयोगिता

अनुच्छेद 20

विद्यार्थियों, प्रशिक्षुओं, प्रोफेसर्स, अध्यापकों तथा अनुसंधानार्थी

द्वारा प्राप्त भुगतान

किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तत्काल पूर्व संविदाकारी राज्य में से किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में उपस्थित था, उसके द्वारा अपने भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उक्त दूसरे राज्य से बाहरी स्त्रों से प्राप्त भुगतान पर उक्त दूसरे राज्य में कर से छूट मिलेगी ।

2. किसी प्रोफेसर, अध्यापक अथवा अनुसंधानार्थी को, जो एक संविदाकारी दूसरे राज्य का दौरा करने के तत्काल पूर्व संविदाकारी राज्य का निवासी था और जो किसी शैक्षिक संस्थान अथवा किसी विद्यालय में अपनी शिक्षा, अनुसंधान अथवा अध्यापन के संबंधित के उद्देश्य से प्रयोजनार्थ राज्य का दौरा करता है, इस प्रकार उसे प्राप्त आय पर उसके कार्य-कलापों को प्रथम दो वर्षों की अवधि के दौरान प्रयोजनार्थ राज्य में कर नहीं लगेगा ।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंध ऐसे अनुसंधान से प्राप्त आय पर लागू नहीं होंगे यदि ऐसा अनुसंधान मूलतः किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के प्रयोजनार्थ किया गया हो ।

अनुच्छेद 21

अय्य आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय का ऐसी मदों, जिनका दाय करार के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है, पर केवल उस राज्य में कर लगेगा । किन्तु दूसरे संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाली आय का ऐसी मदों पर उक्त दूसरे राज्य में भी कर लगेगा ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अवल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अथवा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 के उपबंध लागू होंगे ।

अनुच्छेद 22

दोहरे कराधान का उपाकरण

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में प्रवृत्त कानून संबंधित संविदाकारी राज्यों में आय के कराधान के मामलों में ऐसे मामलों को छोड़कर लागू रहेंगे लेकिन जहां तक करार में उनके विपरीत कोई प्रावधान किया जाता है ।

2. भारत के मामले में दोहरे कराधान का परिहार निम्नानुसार किया जाएगा :—

(क) जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर करार के उपबंधों के अधीन सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ में कर लगाया जा सकता है, उस स्थिति में भारत उस निवासी को सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ में भ्रष्टा किए गए आयकर, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से दिया गया हो अथवा कटौती के द्वारा दिया गया हो, की राशि के बराबर कर से कटौती की अनुमति देगा । लेकिन ऐसी कटौती आयकर के उतने भाग (जिसकी अवशेषी कटौती की अनुमति दिए जाने से पूर्व की गई थी), से अधिक नहीं होगी जो उस आय के कारण हुई हो जिस पर सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ में कर लगाया जा सकता है ।

(ख) जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस करार के उपबंधों के अधीन केवल सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ में कर लगाया जा सकता है, उस स्थिति में भारत इस आय को कर-आधार में शामिल करेगा लेकिन आयकर में से आयकर के उतने भाग की कटौती की अनुमति देगा जो सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ में उद्भूत हुई आय के कारण बनता हो ।

3. सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ में दोहरे कराधान का उपाकरण सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के कानूनों के अनुसार किया जाएगा और भारत में भ्रष्टा किए गए अथवा छोड़े गए करों पर यथोचित ध्यान दिया जाएगा ।

अनुच्छेद 23

संघबन्धन

1. एक संविदाकारी राज्य दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी के संबंध में उस कर से अपेक्षाकृत अधिक भारी धरकम कर नहीं लगायेगा जो वह राज्य किसी तीसरे राज्य के निवासी के संबंध में लगाए जिसके साथ उसने कोई करारान्तरण के निवारण के लिए करार निष्पन्न नहीं किया।

2. इस अनुच्छेद में "करारान्तरण" पद से अभिप्रेत है इस करार के अंतर्गत आने वाले कर।

अनुच्छेद 24

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहाँ किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी यह समझता है कि दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों राज्यों की कार्यवाही के कारण उस पर जो कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा, वह इस करार के अनुरूप नहीं है, तो वह उन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों पर उपबंधित उपायों के होते हुए भी अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के पास प्रस्तुत कर सकता है, जिसका कि वह निवासी है। यह मामला उस कार्यवाही का प्रथम अधिवक्ता के तीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके कारण उस पर इस प्रकार का कर लगाया जाता है जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित प्रतीत हो और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुँचने में असमर्थ हो, तो वह ऐसे आधान के परिहार की दृष्टि से जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार किए गए समझौते को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे दोनों संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में कोई भी समय सीमा क्यों न हो।

3. इस करार के अर्थानुरूपण की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाई अथवा शक उत्पन्न हो, तो दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, उन्हें पारस्परिक समझौते से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में बाँटने के आधान के उपकरण के लिए परस्पर विचार विमर्श कर सकते हैं, जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गई है।

4. पूर्वोक्त पैराग्राफ के अधिप्राय से किसी समझौते पर पहुँचने के अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी संस्थापित प्रक्रिया के अन्तर्गत, एक दूसरे के साथ सीधे पत्र व्यवहार कर सकते हैं। जब समझौते पर पहुँचने के लिए विचारों का मौखिक आदान प्रदान उचित प्रतीत होगा तो ऐसा आदान प्रदान किसी आयोग के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों।

अनुच्छेद 25

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, अपने-अपने स्वदेशकानूनों के अन्तर्गत सीमा तक ऐसी सूचना (जिनमें दस्तावेज भी शामिल हैं) का आदान-प्रदान करेंगे जो इस प्रकार के उपबंधों की अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित आन्तरिक कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है, जो इस करार के अन्तर्गत आते हैं, जहाँ तक कि उनके अधीन विद्यमान करारान्तरण व्यवस्था करार के प्रतिकूल नहीं हो। कि विशेष रूप से ऐसे करों की जालसाजी अथवा धोखाधड़ी को रोकें जा सकें। किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उन्नीस वर्षों के लिए सुरक्षित रहेगी।

प्रकार गोपनीय मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के आन्तरिक कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है। लेकिन, यदि सूचना सेजने वाले राज्य में सूचना को मूलतः गोपनीय समझा जाता है, तो उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो उन करों का निर्धारण अथवा उनकी समीक्षा करने, उनके प्रवर्तन अथवा अधिव्ययन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपराधों का निर्धारण करने में सहायक हों, जो करार के विषय हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए करेंगे परन्तु वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय को कार्यवाही अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। सूचना अथवा दस्तावेज का आदान प्रदान मामलों विशेष के संबंध में अनुरोध करने पर किया जा सकेगा।

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों अथवा प्रशासनिक प्रथा से उत्पन्न प्रशासनिक उपाय करना,

(ख) ऐसी सूचना को सफाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत अथवा प्रशासन को सामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं है।

(ग) ऐसी सूचना को सफाई करना जिनसे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो अथवा जिसको प्रकट करना प्रभावित राज्य के हितों के प्रतिकूल है।

3. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे को उनके अपने-अपने कर कानूनों में किए गए परिवर्तनों की सूचना देंगे।

अनुच्छेद 26

राजनीतिक और नैतिकता

इस करार में किसी भी बात से राजनीतिक अथवा आर्थिक अथवा नैतिकता के अन्तर्गत कानून के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय विशेष अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 27

मौजूदा करार

इस करार की किसी भी बात से संविदाकारी राज्यों के बीच मौजूदा करारों के उपबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिवाय उन करों को छोड़ कर जिन पर यह करार लागू होता है किन्तु जहाँ इस करार के किसी उपबंध से उन करों से अपेक्षाकृत अधिक राहत मिलती है, उस स्थिति में उचित उपबंध लागू होगा।

अनुच्छेद 28

प्रवर्तन

दोनों संविदाकारी राज्यों में से प्रत्येक राज्य, इस प्रकार को लागू करने के लिए अपने विधि के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यविधियों के पूरा किए जाने के बारे में दूसरे राज्य को अधिव्ययन करेगा। यह करार इन अधिसूचनाओं में से बाव में जारी की गई अधिसूचना की प्राप्ति को तत्पश्चात् से लागू होगा और इसका निम्नलिखित प्रभाव होगा:

(क) भारत में, उस कैलेंडर वर्ष के, जिसमें यह करार प्रवृत्त हुआ है, अगले मुवर्ती वर्ष के प्रथम माह के प्रथम दिनांक को अथवा

उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी वित्त वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में ;

- (ख) सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ में, उस कैलेंडर वर्ष के, जिसमें यह करार प्रवृत्त हुआ है, अगले अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी वित्त वर्ष में उद्भूत हुई आय के संबंध में ।

अनुच्छेद 29

समाप्ति

1. यह करार अनिश्चित काल तक लागू रहेगा लेकिन दोनों संबिवाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी भी कैलेंडर वर्ष के जून माह के तीसरे दिन को, अथवा उससे पहले राजनयिक अधिकारियों से दूसरे संबिवाकारी राज्य को इसकी समाप्ति का लिखित रूप में नोटिस दे सकेगा और ऐसी स्थिति में यह करार निम्नलिखित के लिए निष्प्रभावी हो जाएगा :

- (क) भारत में उस कैलेंडर वर्ष के, जिसमें समाप्ति की सूचना दी जाती है, अगले अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी वित्त वर्ष में उद्भूत हुई आय के संबंध में ;
- (ख) सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ में, उस कैलेंडर वर्ष के, जिसमें समाप्ति का नोटिस दिया जाना है, अगले अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी वित्त वर्ष में उद्भूत हुई आय के संबंध में ।

जिसके साथ में, इसके लिए विधिवत प्राधिकृत अधिकारियों ने इस वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में एक हजारवीं सी अटठासी के नवम्बर माह के बीसवें दिन हिन्दी, रूसी और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में सम्पन्न किया गया । इसके सभी पाठ समानतः प्रामाणिक हैं । इन पाठों में से किसी भी पाठ के बीच भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा ।

भारतीय गणराज्य की सरकार सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की ओर से की सरकार की ओर से

न.

न.

(एस. बी. खन्ना)

(बी. एम. कोमेन्तसेव)

अधिसूचना सं. 8442-का.सं. 503 1-88 एफ.टी.डी.)

पी. के. अय्यायू, पंयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(FOREIGN TAX DIVISION)

New Delhi, the 4th September, 1989

NOTIFICATION

INCOME-TAX

G.S.R. 812 (E).—Whereas the annexed Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Union of Soviet Socialist Republics for the avoidance of double taxation of income has come into force on the 5th June, 1989,

after the notification by both the Contracting States to each other of the completion of the procedures required under their laws for bringing into force of the said Agreement in accordance with Article 28 of the said Agreement ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby direct that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India

ANNEXURE

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION OF INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of the Union of Soviet Socialist Republics.

led by the desire to strengthen and develop friendly relations in economic, industrial, technical and cultural spheres,

have resolved to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation of income,

and have agreed as follows :

ARTICLE 1

Scope of the Agreement

1. This Agreement shall apply to persons who for the purposes of taxation are deemed to be residents of one or both of the Contracting States.

2. (a) This Agreement shall apply to the territory of each Contracting State, including its territorial sea, to its economic zone and its continental shelf, adjacent to the limits of its territorial sea, in respect of which it exercises, in conformity with international law, sovereign rights for the purpose of exploration and exploitation of natural resources of such areas ;

(b) For the purposes of this Agreement any reference to either Contracting State shall be deemed as reference to the territory of the respective State, including its territorial sea, to its economic zone and the regions of the continental shelf adjacent to the limits of the territorial sea of this State, which are mentioned in sub-paragraph (a).

ARTICLE 2

Taxes Covered

1. The taxes to which this Agreement shall apply are :—

(a) in the Republic of India, the income tax including any surcharge thereon (hereinafter referred to as "Indian tax") ;

(b) in the Union of Soviet Socialist Republics :

(i) income tax on foreign legal persons ;

- (ii) income tax on population ; and
- (iii) tax on part of profits of a foreign participant of a joint venture imposed when it is transferred abroad (hereinafter referred as "the USSR tax").

2. The Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Agreement in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 1.

3. Taxes mentioned in this Article shall not include any penalty or interest imposed by either Contracting State relating to the taxes covered by this Agreement.

ARTICLE 3

General Definitions

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires :

(a) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean the Republic of India (India) or the Union of Soviet Socialist Republics (the USSR), as the context requires ;

(b) the term "person" means an individual; and

(i) in the case of India, also a company or any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in India ;

(ii) in the case of the USSR, also any legal person or other organisation, created under the laws of the USSR or any Union Republic and treated as a legal person for the purposes of taxation in the USSR ;

(c) the term "competent authority" means :

(i) in the case of India, the Ministry of Finance (Central Government—Department of Revenue) or its authorized representative ;

(ii) in the case of the USSR, the Ministry of Finance of the USSR or its authorized representative ;

(d) the term "national" means :

(i) in the case of India, any individual possessing the nationality of India and any legal person, partnership or association deriving its status from the laws in force in India;

(ii) in the case of the USSR, any individual possessing the citizenship of the USSR and any legal person deriving its status from the laws in force in the USSR;

(e) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by a resident of a Contracting State except

when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(f) the term "fiscal year" means :

(i) in the case of India, the "previous year", as defined in the Income-Tax Act, 1961;

(ii) in the case of the USSR, the period commencing on the 1st January and ending on the 31st of December.

2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State, any term not defined herein shall unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Agreement applies

ARTICLE 4

Resident

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows :

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

(d) if each Contracting State regards him as a national of that State or if he is a national of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

ARTICLE 5

Permanent Establishment

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means any fixed place of business through which a resident of a Contracting State carries on, wholly or partly, business in the other Contracting State.

2. The term "permanent establishment" includes especially :

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
- (g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;
- (h) a premises used as a sales outlet or for receiving or soliciting orders;
- (i) an installation or structure used for the exploration or exploitation of natural resources;
- (j) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or activities (together with other such sites, projects or activities, if any) continue for a period of more than 6 months or where such project or supervisory activity, being incidental to the sale of machinery or equipment, continues for a period not exceeding 6 months and the charges payable for the project or supervisory activity exceed 10 per cent of the sale price of the machinery and equipment.

However, the competent authorities of the Contracting States may in particular cases and by mutual agreement consider such activities as not constituting a permanent establishment also in case, when the duration of works on a building site or a construction or assembly project exceeds 6 months.

Provided that for the purpose of this paragraph a resident of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State and to carry on business through that permanent establishment if it provides services or facilities in connection with or supplies plant and machinery on hire used or to be used in, the prospecting for, or extraction or production of mineral oils in that other State.

3. Notwithstanding the preceding provision, of this Article the term "permanent establishment" shall not include

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of merchandise for the resident;

- (b) the maintenance of a stock of goods belonging to the resident, only for the purpose of storage or display ;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the resident, solely for the purpose of processing by another person ;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purchase of goods or merchandise or for collecting information for the resident ;
- (e) subject of the provisions of sub-paragraph (j) of paragraph 2 of this Article, carrying out of mere supervision for a period not exceeding 6 months over construction and assembly works ;
- (f) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying out of advertising or scientific research or any other activity of a preparatory or an auxiliary character, for the resident ;
- (g) the maintenance of a fixed place of business for the display of goods and merchandise belonging to the resident, at occasional exhibitions ;
- (h) the maintenance of a fixed place of business solely for carrying out, for the resident, one or several kinds of activity enumerated in sub-paragraphs (a) to (g), if the activity, being the result of carrying out of overall activity being the result of carrying out of these kinds of activity, is of a preparatory or an auxiliary character.

However, the provisions of sub-paragraphs (a) to (h) shall not be applicable where the resident of a Contracting State maintains any other fixed place of business in the other Contracting State for any purposes other than the purposes specified in the said sub-paragraphs.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 where a person—other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies—acting in a Contracting State on behalf of a resident of the other Contracting State, that resident shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned State, if:—

- (a) he has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts on behalf of the resident, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the resident ;
- (b) he has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the resident ;
- (c) he habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the resident itself or for the resident and other residents controlling, controlled by, or subject to the same common control, as the resident ; or

- (d) in so acting, he manufactures or processes in that State for the resident goods or merchandise belonging to the resident.

5. A resident of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. The fact that a person (other than an individual) who is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a person (other than an individual), who is a resident of the other Contracting State or who carries on business in that other State (either through a permanent establishment or otherwise) shall not constitute one of these persons a permanent establishment of the other.

ARTICLE 6

Income from Immovable Property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term, in the case of India, shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources.

Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of a resident and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

ARTICLE 7

Business Profits

1. The profits of a resident of Contracting State shall be taxable only in that State unless the resident carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the resident carries on business as aforesaid, the profits of he resident may be taxed in the other State but only so much of them as is directly or indirectly attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where a resident of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent

establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate resident engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the resident of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the taxation laws of that State.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the resident.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other articles of this Agreement, then the provisions of those articles shall not be affected by the provisions of this article.

7. Where :—

(a) a resident of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of a resident of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of a resident of a Contracting State and a resident of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two such residents in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent residents, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the residents, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that resident and taxed accordingly.

ARTICLE 8

Air Transport

1. Profits derived by a resident of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

3. For the purposes of this Article, interest on funds connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such aircraft, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

4. The term "operation of aircraft" shall mean business of transportation by air of passengers, mail, livestock or goods, carried on by the owners or lessees or charterers of aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft and any other activity directly connected with such transportation.

ARTICLE 9

Shipping

1. Income derived by a resident of a Contracting State from the operation of ships in international traffic shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article and Article 15 of the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Union of Soviet Socialist Republics on Merchant Shipping, dated 19 July 1976, income derived by a resident of a Contracting State from the operation of ships between the ports of the other Contracting State and the ports of third countries (in both directions) may be taxed in that other State, but the tax imposed in that other State shall be reduced by an amount equal to two third thereof.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply to income from participation in a pool, a joint business or an international operating agency engaged in the operation of the ships.

4. For the purposes of this Article:—

- (a) interest on funds connected with the operation of ships in international traffic shall be regarded as income from the operation of such ships and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest ; and
- (b) income from the operation of ships includes income derived from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of goods or merchandise in international traffic.

ARTICLE 10

Dividends

1. Dividends paid by a legal person (in the case of India, a company) which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the legal person (in the case of India, a company) paying the dividends

is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.

This paragraph shall not affect the taxation of the legal person (in the case of India, a company) in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the legal person (in the case of India, a company) making the distribution is a resident. In the case of the USSR, this term especially part of profits of a joint venture established in conformity with the laws of the USSR which is attributable to its participant who is a resident of India, transferred from the USSR.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the legal person (in the case of India, a company) paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case, the provisions of Article 7 shall apply.

ARTICLE 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

Notwithstanding the provisions of paragraph 2,—

(a) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by :

(i) the Government, a sub-division or a local authority of the other Contracting State;

or

(ii) the central bank of that other State ;

(b) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State to the extent approved by the Government of that State if it is derived and beneficially owned by any person (other than a person referred to in sub-paragraph (a) who is a resident of the other Contracting State provided that

the transaction giving rise to the debt-claim has been approved in this regard by the Government of the first-mentioned State.

4. The term "interest" when used in this Article means income from debt-claims of every kind, bank deposits, Government loans as well as any other income which is treated as interest in accordance with the laws of the State where such income arises. Penalty charges for the payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 12

Royalties and Fees for Technical Services

1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed :

- (a) 15 per cent of the gross amount of the royalties relating to copyrights of literary, artistic or scientific works, other than cinematograph films or films or tapes used for radio or television broadcasting ; and

- (b) 20 per cent of the gross amount of the royalties in all other cases or fees for technical services.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, formula or process, or for the use of or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any kind to any person other than payments to an employee of a person making payments, in consideration for the services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provision of services of technical or other personnel.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

6. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or no, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated.

Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties or fees for technical services paid exceeds the amount which would have been paid in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 13

Gains from Alienation of Property

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which a resident of a Contracting State has in the other Contracting State including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole property), may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a legal person (in the case of India, a company) which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

5. Gains from the alienation of any property other than that mentioned in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

ARTICLE 14

Independent Personal Services

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the performance of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he is present in the other Contracting State for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 90 days in the relevant fiscal year, in that case, such income may also be taxed in that other State, but only so much of it as is derived from his activities performed in that other State.

2. The term "professional services" includes especially independent personal services of an individual in his capacity as a physician, teacher, architect, engineer and accountant.

ARTICLE 15

Income from Employment

1. Subject to the provisions of Articles 16, 17, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first mentioned State if :—

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant fiscal year;

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised abroad a ship or aircraft operated in international traffic by a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

ARTICLE 16

Directors' Fees

Directors' fees and similar payment derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or similar body of a company or any other legal person which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 17

Income Earned by Entertainers and Athletes

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of Contracting State as an entertainer such as a theatre, motion picture, radio or television artiste or a musician or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Where such income in respect of personal activities exercised by an entertainer or athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or an athlete who is a resident of a Contracting State from his personal activities as such exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State, if more than 50 per cent of the expenses for such activities are supported from the public funds of the first-mentioned State, including any of its sub-divisions or local authorities.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 and Articles 7, 14 and 15, where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such in a Contracting State accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State if more than 50 per cent of the expenses of such person are supported from the public funds of that other State including any of its sub-divisions or local authorities.

ARTICLE 18**Remuneration and Pensions in Respect of Government Service**

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State, or a sub-division or a local authority thereto to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other contracting State, if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:

- (i) is a national of that State; or
- (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by a Contracting State, or a sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of that other State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 19 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with commercial activities.

ARTICLE 19**Pensions**

Any pension, other than a pension referred to in Article 18, derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the first-mentioned State.

ARTICLE 20**Payment Received by Students, Apprentices, Professors, Teachers and Research Scholars**

1. A student or business apprentice who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other contracting State and who is present in that other State solely for the purpose of his education or training, shall be exempt from tax in that other State on payments derived from sources outside that other State for the purpose of his maintenance, education or training.

2. Remuneration derived by a professor, a teacher or a research scholar who was, immediately before the visit to a Contracting State, a resident of the other Contracting State and visits the first-mentioned State with the aim of promoting his education, conducting research or teaching in an educational institution or a school shall not be taxable in the first-mentioned State during first two years of his activity.

3. The provisions of paragraph 2 shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

2418GI/89-2

ARTICLE 21**Other Income**

1. Items of income of a resident of a Contracting State which are not expressly dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State. However, such items of income arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case, the provisions of Article 7, shall apply.

ARTICLE 22**Elimination of Double Taxation**

1. The laws in force in either of the Contracting States will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in his Agreement.

2. In the case of India, double taxation shall be avoided as follows:

(a) Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the USSR, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in the USSR, whether directly or by deduction. Such deduction shall not, however, exceed that part of income tax (as paid before the deduction is given), which may be attributable to the income which may be taxed in the USSR;

(b) where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, shall be taxable only in the USSR, India may include this income in the tax base but shall allow as a deduction from the income tax that part of the income tax which is attributable to the income derived from the USSR.

3. In the USSR, double taxation shall be eliminated in accordance with the laws of the USSR, due regard being had to the taxes paid or spared in India.

ARTICLE 23**Non-Discrimination**

1. A Contracting State may not exercise in respect of a resident of the other Contracting State a higher or more burdensome taxation than taxation which that State would exercise in respect of a resident of a third State with which it did not conclude an Agreement for the avoidance of double taxation.

2. In this Article the term "taxation" means taxes covered by this Agreement.

ARTICLE 24

Mutual Agreement Procedure

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Agreement. Any Agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other, under the established procedure, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

ARTICLE 25

Exchange of Information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange, to the extent permitted by their domestic laws, such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement, in so far as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. Any information received by a Contracting State shall be treated as confidential in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State. However, if the information is originally regarded as confidential in the transmitting State, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may

disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The exchange of information or documents shall also be on request with reference to particular cases.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State ;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or the other Contracting State ;
- (c) to supply information which would disclose any trade, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to the interests of the first-mentioned State.

3. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of the changes which are made in their tax laws.

ARTICLE 26

Diplomatic and Consular Activities

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

ARTICLE 27

Existing Agreements

Nothing in this Agreement shall affect the provisions of existing agreements between the Contracting States to the extent that they have effect in respect of the taxes to which this Agreement applies. However, where any greater relief from these taxes is afforded by any provision of this Agreement, that provision shall apply.

ARTICLE 28

Entry into Force

Each of the Contracting States shall notify each other of the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the later of these notifications and shall thereupon have effect :

- (a) in India, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the Agreement enters into force;
- (b) in the USSR, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the Agreement enters into force.

ARTICLE 29

Termination

1 This Agreement shall remain in force indefinitely, but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination, and, in such event, this Agreement shall cease to have effect :

- (a) in India, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice of termination is given;
- (b) in the USSR, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at NEW DELHI this 20th day of November, one thousand nine hundred and eighty eight in the Hindi, Russian and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence between any of the texts, the English text shall be the operative one.

For the Government of the Republic of India.

Sd/-

(S. B. CHAVAN)

For the Government of the Union of Soviet Socialist Republics

Sd/-

(V. M. KAMENTSEV)

[Notification No. 8442/F. No. 503/1/88-FTD]

P. K. APPACHOO, Jt. Secy.

